wealth Office and the Scotland Yard alerting the British Government to the fact that some pro-Kashimri militant groups in U. K. were planning to disrupt the match. After the incidents of hooliganism had occurred, our High Commission in London sent a letter to the Foreign and Commonwealth Office and contacted the local police the very same day i.e. on August 30, 1993 requesting legal action to be taken against the culprits. Following this, the police registered a criminal case in the matter and arrested three persons. The matter was also taken up by the Ministry of External Affairs with the British High Commissioner in New Delhi who wholly shared our regret at the incident and assured that he would report the matter to the British Government in London.

Convention on Rights of Children

1129. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are enforcing and promoting various programmes for convention on Rights of Children and if so, the steps taken in this direction and results obtained and achieved; and

(b) whether nutrition of the children is receiving full attention and if so, the details of any Action Plan made, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESWARI): (a) and (b) The Government of India has ratified the UN Convntion on the Rights of the Child. Appropriate legislative and administrative measures are being taken for implementing the Convention by the concerned Ministries/ Departments.

A National Plan of Action on Children has been adopted under which goals have been fixed for the decade 1990-2000. The Plan seeks to cover the programmes in the areas of Child and Maternal Health, Nutrition, Water and Sanitation, Education, Children in difficult circumstances and adolescent girls. All sectors have reviewed their programmes for strengthening keeping in view the goal; set in National Plan of Action on Children.

A number of child care programmes for imporving the nuritional status of child are being implemented. Integrated Child Development Services (ICDS) Programme is a major intervention for providing a package of services including supplementary nutrition to 1.63 crores children under 6 years of age. Nutrition supplementation is also being provided to children under the scheme of creches (3 lakhs children) and Balwadi Nutrition (2.29 lakhs children). A new initiative to improve nutritional stutus of adolescent girls has been statred, on a selected basis, in 507 ICDS Projects. Again, through nutrition education programmes the mothers also being educated and empowered to look after the nutritional needs of their children better.

The Department has identified 180 focal districts in country based on criteria of poverty, concentration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and high crude birth rate. While expanding Child Care Programmes, preference is given to these focal districts. A State-wise list of the focal districts is given in the annexure. (*See* Appendix CLXIX, Annexure No. 28)

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जाना

1130. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु हिमाचल प्रदेश में कतिपय विद्यालयों का चयन किया है और ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए है; यदि हां, तो उन प्रतिनिधियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां। खलों के संवर्धन के लिए हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल का चयन किया गया है ;

(ख) से (घ) शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भारतीय खेल प्राधिकरण पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलों के विकास के लिए वर्ष 1987 में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्कूल, माजरा, हिमाचल प्रदेश को अपनाया है। योजना के अंतर्गत राज्य से चुने गए छः बच्चों को स्कूल में दाखिल किया गया है ।

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

1131. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को देश में नये नवोदय विद्यालय खोलने हेतु विभिन्न राज्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या-क्या हैं जो नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार के विचाराधीन हैं और उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस वर्ष नये नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यवार जिलों के नामों को, जहां 1993–94 के दौरान नवोदय विद्यालयों का प्रस्ताव किया गया खोले गए हैं, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिए**) । नवोदय विद्यालय तभी खोले जाते हैं जब सम्बंधित राज्य सरकार पर्याप्त और उपयुक्त भूमि, समिति द्वारा अपना भवन बना लिए जाने तक विद्यालयों को चलाने के लिए कम से कम 2–3 वर्षों के लिए अस्थायी आवास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करा देती हैं।

विवरण

1993–94 के दौरान खोले जाने के लिये स्वीकृत/प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों/ जिलों के नाम

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों का नाम	
		स्वीकृत	प्रस्तावित
1.	असम	1. नालाबाडी 2. कामरूप	1. शिवसागर
2.	आन्ध्र प्रदेश	3. महबूबनगर	2. हैदराबाद
3.	अरूणाचल प्रदेश	4. त्वांग	3. लोअर सुबंसिरि 4. पश्चिमी सियांग